

Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata – 700 001

Serial Circular No. 160/2016

No. E.368/0/ACP/Pt.V

Kolkata, Dated: 21/12/2016

ALL CONCERNED

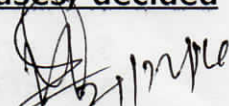
(As per the standard List)

Sub: Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) for the Railway Employees – Implementation of seventh CPC recommendations.

Railway Board's letter No. **PC-V/2016/MACPS/1** dated 19.12.2016 (**RBE No.155/2016, S. No. PC-VII/12**) is forwarded herewith for information and necessary action. Board's earlier letter dated 10.06.09 (RBE No.101/2009) mentioned therein was circulated under this office serial No. **102/2009**.

In terms of the aforesaid instructions, for grant of financial upgradation under the MACPS, the prescribed benchmark would be '**Very Good**' for all the posts and would be effective **from 25th July, 2016**. Further, MACPS where it was due earlier to 25.07.2016, but not decided yet due to Administrative delay, will be decided as per criteria at that time. Cases that became due on or after 25.07.2016 will be decided as per new criteria. However, **Past cases, decided otherwise, need not be re-opened.**

DA: Hindi Version.


(S. Chakraborty)
Sr. Personnel Officer/BGB
For Chief Personnel Officer
Phone No. 24115

Copy of Board's letter No. PC-V/2016/MACPS/1 dated 19.12.2016 (RBE No.155/2016, S. No. PC-VII/12) addressed to GMs/All Indian Railways & PUs.

Sub: Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) for the Railway Employees – Implementation of seventh CPC recommendations.

The Modified Assured Career Progression Scheme was introduced with effect from 01.09.2008 in pursuance of the recommendations of the Sixth Pay Commission by this Ministry's letter No. PC-V/2009/ACP/2 dated 10.06.2009 (RBE No. 101/2009). Thereafter, subsequent amendments/clarifications were issued from time to time. These instructions are in force with effect from 01.09.2008.

2. The 7th Central Pay Commission (CPC) in para 5.1.44 of its report has recommended inter-alia as follows:

"MACP will continue to be administered at 10, 20 and 30 years as before. In the new Pay Matrix, the employee will move to immediate next level in hierarchy. Fixation of pay will follow the same principle as that for a regular promotion in the Pay Matrix. MACPS will continue to be applicable to all employees up to Higher Administrative Grade (HAG) level except members of Organised Group 'A' Services."

Contd..

3. The Government has considered the above recommendation and has accepted the same. In the light of the recommendations of the 7th CPC accepted by the Government, the Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) will continue to be administered at 10, 20 and 30 years as before. Further, Para 1 and 2 of the existing Scheme (Annexure to this Ministry's letter No. PC-V/2009/ACP/2 dt. 10.06.2009) will be substituted by the following words:-

1. There shall be three financial upgradations under the MACPS as per 7th CPC recommendations, counted from the direct entry grade on completion of 10, 20 and 30 years services respectively or 10 years of continuous service in the same level in Pay Matrix, whichever is earlier.

2. The MACPS envisage merely placement in the immediate next higher level in the Pay Matrix as given in PART A of Schedule of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016. Thus, the level in the Pay Matrix at the time of financial upgradation under the MACPS can, in certain cases, be different than what is available at the time of regular promotion in one's own AVC. In such cases, the higher level in the Pay Matrix attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/organization will be given only at the time of regular promotion."

4. The 7th Central Pay Commission (CPC) in para 5.1.45 of its report has inter-alia recommended as follows:

"Benchmark for performance appraisal for promotion and financial upgradation under MACPS to be enhanced from 'Good' to 'Very Good'."

5. The Government has considered the above recommendation and has accepted the same. In the light of the recommendations of the 7th CPC accepted by the Government, para 17 of the Scheme (Annexure to Board's letter No. PC-V/2009/ACP/2 dt. 10.06.2009) shall be substituted by the following words:-

"17. For grant of financial upgradation under the MACPS, the prescribed benchmark would be 'Very Good' for all the posts."

6. These changes will come into effect from 25th July, 2016, i.e., from the date of resolution notified by Department of Expenditure, Ministry of Finance regarding acceptance of the recommendations of the 7th CPC.

6.1. MACPS where it was due earlier to 25.07.2016, but not decided yet due to Administrative delay, will be decided as per criteria at that time. Cases that became due on or after 25.07.2016 will be decided as per new criteria. However, Past cases, decided otherwise, need not be re-opened.

7. The comprehensive MACP Scheme on acceptance of Seventh Central Pay Commission recommendations will be issued separately.

8. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

9. Hindi version is enclosed.

(Authority: DoP&T's OM No. 35034/3/2015-Estt.(D), dt.28.09.2016)

**Sd/- (N. P. Singh),
DD, PC-V/Rly. Board**

Index No.1060: For grant of financial upgradation under the MACPS in 7th CPC, the prescribed benchmark would be 'Very Good' for all the posts.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्र. सं. पीसी-VII/12

सं. पीसी-V/2016/एमएसीपीएस/1

आरबीई सं. 155/2016

नई दिल्ली, दिनांक 19.12.2016

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

(डाक-सूची के अनुसार)

विषय: रेल कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना (एमएसीपीएस) - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना।

इस मंत्रालय के दिनांक 10.06.2009 के पत्र सं. पीसी-V/2009/एसीपी/2 (आरबीई सं. 101/2009) द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 01.09.2008 से संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना लागू की गई। उसके बाद समय-समय पर संशोधन/स्पष्टीकरण जारी किए गए। ये अनुदेश 01.09.2008 से लागू हैं।

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.44 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार सिफारिश की है:

"एमएसीपी पहले की तरह 10, 20 और 30 वर्ष पर दी जाती रहेगी। नए वेतन मैट्रिक्स में, कर्मचारी पदानुक्रम में ठीक अगले लेवल में चला जाएगा। वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के लिए वही सिद्धांत अपनाया जाएगा जो नियमित पदोन्नति के लिए अपनाया जाता है। एमएसीपीएस संगठित समूह 'क' सेवाओं के सदस्यों को छोड़कर उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) स्तर तक सभी कर्मचारियों के लिए लागू रहेगी।"

3. सरकार ने उपर्युक्त सिफारिश पर विचार किया है और उसे स्वीकार किया है। सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना (एमएसीपीएस) पहले की भाँति 10, 20 और 30 वर्षों में प्रदान की जाती रहेगी। इसके अलावा, मौजूदा योजना (इस मंत्रालय के दिनांक 10.06.2009 के पत्र सं. पीसी-V/2009/एसीपी/2 का अनुलग्नक) के पैरा 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"1. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, एमएसीपीएस के अंतर्गत तीन वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किए जाएंगे जिनकी गणना सीधे प्रवेश ग्रेड से क्रमशः 10, 20 और 30 वर्ष अथवा पे मैट्रिक्स में एक ही लेवल पर 10 वर्षों की निरंतर सेवा, जो भी पहले हो, पूरी होने पर की जाएगी।

2. जैसाकि रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग 'ए' में दिया गया है, एमएसीपीएस में केवल पे मैट्रिक्स में निकटतम अगले उच्चतर लेवल पर रखने की अवधारणा है। इस प्रकार, कुछ मामलों में जहां पे मैट्रिक्स में दो क्रमागत लेवलों के

बीच किसी व्यक्ति के अपने एवीसी में नियमित पदोन्नति उपलब्ध नहीं होती है, वहां एमएसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन के समय पे मैट्रिक्स में लेवल, नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध लेवल से भिन्न हो सकता है। ऐसे मामलों में, संबंधित संवर्ग/संगठन के पदानुक्रम में अगली पदोन्नति पद से सम्बद्ध पे मैट्रिक्स में उच्चतर लेवल केवल नियमित पदोन्नति के समय दिया जाएगा।"

4. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.45 में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सिफारिश की है:-

"प्रोन्नति तथा एमएसीपीएस के अन्तर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन के लिए कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए बेंचमार्क 'अच्छा' से बढ़ाकर 'बहुत अच्छा' किया जाएगा।"

5. सरकार ने उपर्युक्त सिफारिश पर विचार किया है और उसे स्वीकार किया है। सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में इस योजना (बोर्ड के दिनांक 10.06.2009 के पत्र सं. पीसी-V/2009/एसीपी/2 का अनुलग्नक) के पैरा 17 के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"17. एमएसीपीएस के अन्तर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने के लिए सभी पदों के लिए निर्धारित बेंचमार्क "बहुत अच्छा" होगा।"

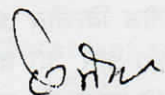
6. ये परिवर्तन 25 जुलाई, 2016 अर्थात् सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संकल्प अधिसूचित करने की तारीख से प्रभावी होंगे।

6.1 जहां 25.07.2016 से पहले एमएसीपीएस देय था परन्तु उन पर प्रशासनिक विलंब के कारण अभी निर्णय नहीं लिया गया है, ऐसे मामलों में निर्णय उस समय मौजूद मानदण्ड के अनुसार लिया जाएगा। ऐसे मामलों, जहां 25.07.2016 को अथवा उसके बाद एमएसीपीएस देय था, में नए मानदण्ड के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल, विगत में अन्यथा निर्णीत मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।

7. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने से संबंधित व्यापक एमएसीपी स्कीम को अलग से जारी किया जाएगा।

8. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

{कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 28.09.2016 का का.जा.सं. 35034/3/2015-ईस्ट(डी)}



(एन.पी. सिंह)

उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड